



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 21, 2017/श्रावण 30, 1939

No. 217]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 2017/ SRAVANA 30, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2017

डिजिधन मिशन

फा. सं. 3(4)/2017-ईजी II.—1.1 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नागरिकों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्रशासन और डिजिटल सेवा उपलब्ध करा कर भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक सहज विस्तार है और इसमें वित्तीय लेनदेनों को औपचारिक बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता मौजूद है।

1.2 वित्तीय समावेशन भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है डिजिटल भुगतान प्रणालियां ई-कॉमर्स से औपचारिक वित्तीय सेवाओं और लाभों तक पहुंच का वादा करती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लगातार बाहर रखा जाना जारी है। बैंक-आधारित भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भी, बुनियादी भुगतान सेवाओं की उपलब्धता में काफी अंतर बना हुआ है। प्रौद्योगिकी को अपनाने से देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है।

1.3 भारत वर्तमान में एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के सृजन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जनता के बीच मोबाइल फोनों के तेजी से प्रसार के साथ-साथ डिजिटल प्रौद्योगिकियों, सिग्नल के प्रसार और विस्तार के फलस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसे मजबूत, सुरक्षित और समावेशी डिजिटल भुगतान परिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के लिए सरकार द्वारा एक केन्द्रित पहल आवश्यक है, जिसका अभिगम समाज के सभी वर्गों द्वारा किया जा सकता है।

1.4 वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2017 को अपने बजट भाषण में "यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के माध्यम से वर्ष 2017-18 के लिए 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेन का लक्ष्य" घोषित किया था और इस बात की घोषण की थी कि इस प्रयोजन से एक समर्पित मिशन की स्थापना की जाएगी।

1.5 इस विज्ञान के अनुक्रम में सरकार एतद्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन डिजिधन मिशन नामक एक समर्पित मिशन की स्थापना कर रही है।

2. उद्देश्य और कार्य

डिजिधन मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य और कार्य होंगे:

I. उद्देश्य

2.1 यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेन का लक्ष्य प्राप्त करना।

2.2 एक मजबूत, सुरक्षित समावेशी राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान परिस्थितिकि तंत्र की स्थापना, वृद्धि और स्थायित्व को बढ़ावा देना और उसकी निगरानी करना।

2.3 सरकार की डिजिटल भुगतान से सेवा प्रदायगी, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और रसीद (ईपीआर) और प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) कार्यक्रम के लिए आवश्यक समर्थकारी और अवसंरचना सृजित करना।

2.4 दक्ष,वहनीय और सुरक्षित डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए उपयुक्त मानक तैयार करना और उन्हें सुकर बनाना।

2.5 डिजिटल भुगतान परिस्थितिकि तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

2.6 नए डिजिटल भुगतान उत्पदों, प्लेटफॉर्मों, सेवाओं और स्थीय प्रदायगी मॉडलों के विकास सहित अनुसंधान और नवोदभव को बढ़ावा देना।

II. कार्य

2.7 डिजिटल भुगतान लेने देनों से संबंधित मौजूदा संस्थागत, कानूनी, सुरक्षात्मक, नीतिगत और नियामक ढांचों की समीक्षा करना;आवश्यक होने पर परिवर्तन करना/सुकर बनाना।

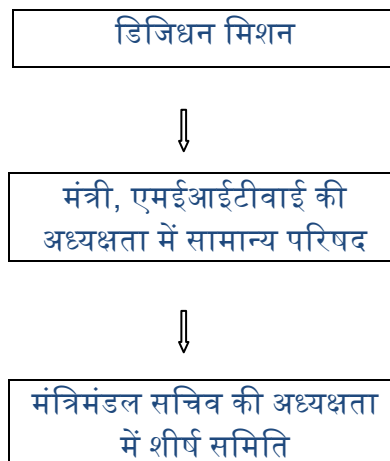
2.8 डिजिटल भुगतानों के लिए संबंधित प्रणाली और बैंक एण्ड प्रौद्योगिकी और स्वीकार्य अवसंरचना का विस्तार करना; डिजिटल भुगतान लेन देनों के लिए नए और व्यवहार्य प्रौद्योगिकी विकल्पों की पहचान करना।

2.9 डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकि तंत्र में आरएण्डडी और नवोन्मेष को सुकर बनाना।

2.10 डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकि तंत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय प्रस्तावित करना।

2.11 लेन-देन प्रभारों को औचित्यपूर्ण बनाने सहित डिजिटल भुगतान लेन-देनों के लिए उपयुक्त वाणिज्यिक और व्यापार मॉडल प्रस्तावित करना।

- 2.12 डिजिटल भुगतानों यंत्रों के प्रयोग; विशेष रूप से भीम और आधार आधारित भुगतान प्रणालियों को चलाने के लिए नागरिकों, व्यापार स्थापना और सरकारी संस्थानों सहित उपभोक्ता समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाना ।
- 2.13 डिजिटल भुगतानों लेन देन को बढ़ाना देने और उनकी अधिक वृद्धि के लिए उपयुक्त उपर्युक्त वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रतिपादित और कार्यान्वित करना ।
- 2.14 सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस), बीमा संबंधी प्रावधानों और सुगम अधिगम के लिए उपयुक्त मानकों और ढांचे को विकसित करके डिजिटल भुगतान यंत्रों में उपभोक्ता के आत्मविश्वास को बढ़ाना ।
- 2.15 अपने संबंधित क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान लेन देनों को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के मंत्रालयों और सर्वजनिक एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- 2.16 डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार के लिए बैंक, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों, भुगतान बैंकों (और अनुज्ञा प्राप्त बैंकों) और अन्य पणधारकों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- 2.17 लोकयुक्त की स्थापना, टोल फ्री हेल्पलाइन और दूसरे उपायों सहित शिकायतों के प्रभावकारी और ठीक समय पर समाधान के लिए उपयुक्त तंत्रों की स्थापना करना ।
- 2.18 डिजिटल भुगतानों के क्षेत्र में कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न उपायों और डिजिटल भुगतानों के पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके प्रभाव की निगरानी करना ।
- 2.19 आवश्यक होने पर कोई अन्य संबंधित या अवशेष नीतिगत उपाय, कार्यक्रम और हस्तक्षेप।
3. मिशन की संरचना
- 3.1 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत डिजिधन मिशन की स्थापना की जा रही है । डिजिधन मिशन की शासन संरचना निम्ननुसार तारीक से होगी :





सचिव, एमईआईटीवाई की
अध्यक्षता में कार्यकारी समिति



डिजिटल मिशन सचिवालय

- 3.2 शीर्ष समिति और कार्यकारी समिति के गठन से संबंधित विवरण क्रमशः अनुबंध 'क' और अनुबंध 'ख' में दिए अनुसार है।
- 3.3 डिजिटल मिशन सचिवालय में एमईआईटीवाई के स्टॉफ और अधिकारियों के साथ-साथ नियामक मामलों, प्रौद्योगिकीय पहलुओं, व्यापार मॉडल, भुगतान अवसंरचना, साइबर सुरक्षा आदि सहित डिजिटल भुगतान से संबंधित मुद्दों पर विषय विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इसमें ऐसा स्टॉफ भी होगा, जो सहक्रिया स्थापित करने और शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अन्य संस्थानों के साथ समन्वय हेतु प्रयासों और उनकी भागीदारी के कार्य का पर्यवेक्षण और निगरानी करेगा।
- 3.4 राज्य स्तरीय समितियाँ: डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने और उनके प्रसार के लिए राज्यस्तरीय उपायों के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता के एक समिति गठित की जाएगी।

4. मिशन का बजट

- 4.1 डिजिटल मिशन अपने कार्यकलापों के लिए आवश्यक होने पर उपर्युक्त स्रोतों, जिनमें डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी वित्तीय समावेशन निधि, विभागीय योजनाएं, बैंक, अन्य निगमित निकाय शामिल हैं, से संसाधनों जुटाएगा।
- 4.2 मिशन के प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक निधियाँ विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के बजटीय प्रावधानों से उपलब्ध कराई जाएगी।

5. मिशन के प्रचालन और रणनीति

- 5.1 डिजिटल मिशन देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्राथमिक लक्ष्य और वित्तिय वर्ष 2017-18 में 2500 करोड़ डिजिटल लेनेदेनी के लक्ष्य को प्राप्त को पूरा करने की दिशा में कार्य करेगा।
- 5.2 इस उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में यह मिशन प्रचालनात्मक दिशानिर्देश जारी करेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाएगा। आवश्यक होने पर मिशन द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् इन्हें जारी किया जाएगा।

राजीव बंसल, संयुक्त सचिव

अनुबंध 'क'

डिजिधन मिशन का गठन: शीर्ष समिति राष्ट्रीय स्तर पर, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति द्वारा डिजिधन मिशन की निगरानी की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया जाएगा:

मंत्रिमंडल सचिव	अध्यक्ष
सीईओ, नीति आयोग	सदस्य
सचिव, वित्तीय सेवा विभाग	सदस्य
सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
सचिव, दूरसंचार विभाग	सदस्य
सचिव, डाक विभाग	सदस्य
सचिव, निवेश और सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग	सदस्य
उप गवर्नर, आरबीआई	सदस्य
सीईओ, यूआईडीएआई	सदस्य
अध्यक्ष, सीबीआई	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, एनपीसीआई	सदस्य
सचिव, एमईआईटीवाई-मिशन निदेशक	सदस्य सचिव

सचिव, एमईआईटीवाई डिजिधन मिशन के मिशन निदेशक और शीर्ष समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के पास शीर्ष समिति में अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित करने और शीर्ष समिति के विशेष आंमत्रिकीयों को बैठकों के लिए बुलाने की शक्ति और प्राधिकार है।

अनुबंध 'ख'

डिजिधन मिशन का गठन : कार्यकारी समिति

डिजिधन मिशन में सचिव, एमईआईटीवाई की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति और निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

सचिव, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष
सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
सचिव, वित्तीय सेवा विभाग	सदस्य
सचिव, दूरसंचार विभाग	सदस्य
सचिव, डाक विभाग	सदस्य
मुख्य सचिव (या उसका/उसकी प्रतिनिधि, जो प्रधान सचिव के स्तर से नीचे नहीं होगा), जो प्रत्येक क्षेत्र से एक राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूर्वोत्तर) प्रत्येक तिमाही के सदस्यता रोटेशन	सदस्य

आधार पर होगी।	
सीईओ, यूआईडीएआई	सदस्य
अपर सचिव, एमईआईटीवाई	सदस्य
डीआईपीपी के प्रतिनिधि, (अपर सचिव के स्तर से नीचे नहीं)	सदस्य
आरबीआई प्रतिनिधि (कार्यकारी निदेशक के स्तर से नीचे नहीं)	सदस्य
मुख्य प्रबन्ध निदेश एनबीएआरडी	सदस्य
महानिदेशक, आई-सर्ट	सदस्य
महानिदेशक, एनआईसी	सदस्य
सलाहकार, नीति आयोग	सदस्य
सीईओ, इंडिया पोस्ट पेयमेंट बैंक	सदस्य
प्रबंध निदेशक, एनपीसीआई	सदस्य
सीईओ, सीससी-एसपीवी	सदस्य
अध्यक्ष, इंडियन बैंक एसोसिएशन	सदस्य
संयुक्त सचिव, एमईआईटीवाई	सदस्य सचिव

समिति के अध्यक्ष के पास आवश्यकता होने पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित करने और कार्यकारी समिति के विशेष आमंत्रिकीयों को भी बैठकों के लिए बुलाने का अधिकार और प्राधिकार होगा।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2017

DIGIDHAN Mission

F.No. 3(4)/2017-EG-II.—1.1 The Digital India Programme envisions transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy by making available digital infrastructure, digital governance and digital services to every citizen. Promotion of a digital payments ecosystem is a natural extension of the Digital India programme and has the potential to transform India's economy by formalization of financial transactions.

- 1.2 Financial inclusion is one of the foremost challenges for India and Digital payments promises access to formal financial services and benefits from e-commerce, especially for those who continue to be excluded. Despite significant progress in bank-led payment systems, there remains a vast gap in the availability of basic payment services. Adoption of technology can transform the country into a cashless economy.
- 1.2 India is currently on the cusp of a radical paradigm transition towards the adoption of technology towards the creation of a digital economy. The rapid proliferation of mobile phones across the population, as well as the rise and spread of digital technologies, signals the need for a focused initiative by the Government for establishing a robust, secure and inclusive pan-India digital payments ecosystem, which can be accessed by all sections of the population.
- 1.3 Hon'ble Finance Minister in his Budget Speech on February 1, 2017 had announced "a target of 2,500 crore digital transaction for 2017-18 through UPI, USSD, Aadhaar Pay, IMPS and debit cards."; and had announced that a dedicated Mission shall be set up for this purpose.

- 1.4 In pursuance of this vision, the Government is hereby setting up a dedicated Mission called the DIGIDHAN Mission under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).

2 Objectives and Functions

The DIGIDHAN Mission would have the following objectives and functions:

I. Objectives

- 2.1 Achieving the target of 2500 crore Digital Payment Transactions in financial year 2017-18 through digital payment modes including UPI, USSD, IMPS, Aadhaar Pay and Debit Cards.
- 2.2 Promoting and overseeing the establishment, growth and sustenance of a robust, secure and inclusive National Digital Payments ecosystem.
- 2.3 Creating requisite enabling infrastructure for Government's Digital Payments Service Delivery, Electronic Payments and Receipts (EPR) and Direct Benefits Transfer (DBT) programme.
- 2.4 Evolving and facilitating appropriate standards for efficient, affordable and secure Digital Payments Services.
- 2.5 Ensuring security of digital payments ecosystem.
- 2.6 Promoting research and innovation, including the development of new digital payment products, platforms, services and sustainable delivery models.

II. Functions

- 2.7 Reviewing the existing institutional, legal, security, policy and regulatory frameworks related to digital payments transactions; and effecting/facilitating changes as required.
- 2.8 Expanding acceptance infrastructure and back-end technology and related systems for digital payments; identification of new and viable technology platforms and options for digital payments.
- 2.9 Facilitating R&D and innovation in the digital payments ecosystem.
- 2.10 Proposing measures to enhance security of digital payments ecosystem.
- 2.11 Proposing appropriate commercial and business models for digital payments including rationalizing transaction charges.
- 2.12 Promoting awareness within user communities including citizens, business establishments and Government organisations to drive usage of digital payments instruments; especially BHIM and Aadhaar based payment systems.
- 2.13 Formulating and implementing appropriate financial incentive programmes and schemes for promotion and greater uptake of digital payments transactions.

- 2.14 Enhancing consumer confidence in digital payments instruments by evolving appropriate standards and frameworks for Quality of Service (QoS), insurance provisions and ease of access.
- 2.15 Coordinating with Ministries of the Union Government, State Governments, and public agencies to promote digital transactions in their respective domains.
- 2.16 Coordinating with Banks, Financial institutions, Fintech companies, Telecom companies, Payments Banks (and other licensed banks) and other stakeholders for expansion of digital payments ecosystem.
- 2.17 Establishing appropriate mechanisms for effective and timely redressal of grievances including establishment of ombudsman, toll-free helplines and other measures.
- 2.18 Monitoring various measures being implemented in the area of digital payments and their impact on the Digital Payments ecosystem.
- 2.19 Any other related or residual policy measures, programmes and interventions that may be required

3 Mission Structure

- 3.1 DIGIDHAN Mission is being setup under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). The governance structure of DIGIDHAN Mission will be as follows:



- 3.2 The details regarding the constitution of the Apex Committee and the Executive Committee are as provided in Annexure A and Annexure B respectively.

- 3.3 The DIGIDHAN Mission Secretariat will comprise of MeitY staff and officers as well as subject matter experts on issues concerning digital payments including regulatory matters, technology aspects, business models, payments infrastructure, cyber security etc. It will also have staff to oversee monitoring and coordination efforts and work in partnership with other institutions to drive synergies and ensure convergence.
- 3.4 State level Committees: At the State level also, there shall be a Committee set-up under the chairmanship of Chief Secretary for implementing State level measures for promotion and proliferation of Digital Payments.

4 Mission Budget

- 4.1 The DIGIDHAN Mission will mobilize resources, as necessary for its activities, from appropriate sources including the Financial Inclusion Fund (FIF), Departments schemes, Banks and other corporate entities involved in the digital transactions ecosystem.
- 4.2 Funds required for administrative purposes for the Mission shall be provided through the budgetary provisions of the Ministry of Electronic and Information Technology (MeitY) following due process.

5 Mission Operations and Strategy

- 5.1 The DIGIDHAN Mission will work towards the primary target of promotion of digital payments in the country and achieving the target of 2500 crore digital transactions in Financial Year 2017/18.
- 5.2 Towards this aim, the Mission would issue operative guidelines and outline the strategy for achieving its objectives. These would be issued, after approval of the Competent Authority, by the Mission as required.

RAJIV BANSAL, Jt. Secy.

Annexure A

Constitution of the DIGIDHAN Mission: Apex Committee

At the national level, the DIGIDHAN Mission shall be monitored by an Apex Committee headed by the Cabinet Secretary and comprising of the following members:

Cabinet Secretary	Chairperson
CEO, Niti Aayog	Member
Secretary, Department of Financial Services	Member
Secretary, Department of Expenditure	Member
Secretary, Department of Telecom	Member
Secretary, Department of Post	Member
Secretary, Department of Investment and Public Asset Management(DIPAM)	Member
Deputy Governor, RBI	Member
CEO,UIDAI	Member
Chairperson, SBI	Member
MD,NPCI	Member
Secretary, MeitY – Mission Director	Member Secretary

Secretary, MeitY will be the Mission Director of DIGIDHAN Mission and Member Secretary of the Apex Committee. The Committee shall have the authority and power to co-opt additional members in the Apex Committee and call upon Special Invitees to the meetings of the Apex Committee

Annexure B

Constitution of the DIGIDHAN Mission: Executive Committee

DIGIDHAN Mission shall comprise of and Executive Committee headed by Secretary, MeitY and comprising the following members :

Secretary, MeitY	Chairperson
Secretary, Department of Expenditure	Member
Secretary, Department of Financial Services	Member
Secretary, Department of Telecom	Member
Secretary, Department of Post	Member
Chief Secretary (or his/her representative not below the level of Principal Secretary) representing one State from each region (North, South, East, West and North East). Membership shall be on rotation basis each quarter	Member
CEO,UIDAI	Member
Additional Secretary, MeitY	Member
Representative of DIPP not below the rank of Additional Secretary	Member
RBI representative (not below the rank of Executive Director)	Member
CMD, NABARD	Member
DG ICERT	Member
DG NIC	Member
Advisor, Niti Aayog	Member
CEO, India Post Payments Bank	Member
MD,NPCI	Member
CEO, CSC – SPV	Member
Chairperson, Indian Banks' Association	Member
Joint Secretary, MeitY	Member Secretary

The Chairperson of the committee shall have the authority and power to co-opt additional members as required and also call upon Special Invitees to the meetings of the Executive Committee.